



2026:AHC:67333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या- 1732 वर्ष 2026

प्रकाश प्रजापति अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: तरुण झा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 50

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव,

जे. रेफरी: आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-01 वर्ष 2026

1. धारा 14-A(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रस्तुत आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश दिनांक 13.01.2026 को एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. और 3(2)(5) के तहत एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना-लहचूरा, जिला झांसी के तहत दायर की गई है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पूरे अभिलेखों का अवलोकन किया। नोटिस की तामील के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि सूचनाकर्ता द्वारा आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके बेटे विशाल अहिरवार का लगभग 18 वर्ष का पप्पू अहिरवार की बेटि के साथ प्रेम संबंध था। आगे यह आरोप लगाया गया है कि 07.08.2025 को लगभग 3.00 बजे अपीलकर्ता प्रकाश प्रजापति सह-आरोपी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अरविंद @ गुल्ले के साथ उसके घर आए और कहा कि वे विशाल के लिए दिल्ली में नौकरी की व्यवस्था करेंगे, इसलिए, वे सूचनाकर्ता के बेटे को ले गए। 07.08.2025 को शाम लगभग 7.00 बजे जब सूचनाकर्ता ने अपने बेटे को फोन किया, जिसने बताया है कि वह तेहलौली शहर में है, उसके बाद, अगले दिन यानी 08.08.2025 को सुबह लगभग 11.00 बजे जब सूचनाकर्ता ने अपने बेटे को फोन किया, तो उसका मोबाइल बंद हो गया। आगे यह आरोप लगाया गया है कि 09.08.2025 को लगभग 11.30 बजे, सूचनाकर्ता अपीलकर्ता के घर गया और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की, अपीलकर्ता ने कहा है कि उसका बेटा अच्छी स्थिति में है। इसके बाद, सूचनाकर्ता को जानकारी मिली कि उसके बेटे का शव झारखंड के पास मिला है। मृतक के शव की पहचान सूचनाकर्ता ने शव परीक्षण हाउस, मौरानीपुर में की है।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि आक्षेपित प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। प्राथमिकी में लगभग दो दिनों की देरी हुई है जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। न तो अपीलकर्ता का नाम प्राथमिकी में है और न ही अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध करने का कोई मजबूत मकसद है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता के नाम का खुलासा केवल सह-आरोपी अरविंद @ गुल्ले के इकबालिया बयान के आधार पर किया गया है। अपीलकर्ता के कब्जे से या उसकी ओर इशारा करने वाली कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है। यह बरामदगी सह-आरोपी अरविंद @ गुल्ले के कब्जे से की गई है और इसका मकसद भी उसके पास है क्योंकि उसकी बहन और मृतक के बीच अवैध संबंध थे। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक ही चोट है जो मृतक की गर्दन में है और सदमे और रक्तस्राव के कारण मृत्यु का कारण बताया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि निकट भविष्य में मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए, अपीलकर्ता को जमानत पर बढ़ाया जा सकता है। अपीलकर्ता 11.08.2025 से जेल में बंद है, जिसका दो मामलों का पिछला आपराधिक इतिहास है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश



दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

5. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की ज़मानत के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने वर्तमान अपराध को यह जानकर किया है कि पीड़ित एस.सी./एस.टी. समुदाय से संबंधित है। आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित पूरे अभिलेखों को ध्यान से देखा है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता के ज़मानत आवेदन को खारिज करने में गलती की। आक्षेपित आदेश दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जा सकता है और अपील की अनुमति दी जा सकती है।

8. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता की ज़मानत याचिका को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध संख्या-में शामिल अपीलकर्ता-प्रकाश प्रजापति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा,

जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।



(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या उस पर संदेह है, जिसके बारे में उस पर संदेह है।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)